

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
जी०बी०पन्त, इंजी० कालेज,
घुड़दौड़ी, पौड़ी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून दिनांक 23 नवम्बर, 2012

विषय:- जी.बी.पंत इंजी० कालेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी में 350 सिंगल सीटर छात्रावास निर्माण के पुनरीक्षित (कट डाउन 120 सीटेड) आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-707/ले०आयो०-पूँजी०परि०/कटडाउन 120सी०छात्रा०, दिनांक 24.07.2012, पत्र संख्या-1090/निर्माण/350सीटेड छा०/2011, दिनांक 24.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-627/XXIV(8)/2006-95/2005, दिनांक 06.11.2006 तथा संख्या-1178/XXIV(8)/2010-95/05, दिनांक 16.09.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जी०बी०पंत इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी, पौड़ी में 350 सिंगल सीटर छात्रावास के निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृत आगणन में कटौती करते हुये 120 सीटर छात्रावास के निर्माण हेतु उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० पौड़ी द्वारा गठित पुनरीक्षित (कट डाउन) आगणन ₹481.53 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹391.93 लाख (रुपये तीन करोड़ इक्यानब्बे लाख तैरानब्बे हजार मात्र) के आगणन की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त कार्य हेतु अब तक अवमुक्त धनराशि ₹362.69 लाख को समायोजित करते हुये, अवशेष ₹29.24 लाख (रुपये उन्नतीस लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वर्तमान में निर्गत की जा रही संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश दिनांक 06.11.2006 द्वारा निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिस्थापन रूप में समझी जायेगी।
- (2) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।
- (3) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (6) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

- (7) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कराया जाना अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (8) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
 - (9) उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समया सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - (10) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चेंकिंग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्ज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।
 - (11) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 - (12) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
2. संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी पौड़ी द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। संबंधित कोषागार बीजक एवं दिनांक की सूचना शासन को तत्काल भेजी जाय।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-00-आयोजनागत-05-इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-126(P)/XXVII(3)/2012-13 दिनांक 05 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग।
5. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० पौड़ी।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एस.एस. टोलिया)
अनुसचिव।